क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 13 | जुलाई 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

हिन्द–अमरीकी साझेदारी हिन्दोस्तानी लोगों के हित में नहीं है

21–23 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर अमरीका की राजकीय दौरे पर जाने वाले हैं। उनके साथ बहुत ख़ास अतिथि के रूप में व्यवहार किए जाने की अपेक्षा की जा रही है। उन्हें दूसरी बार अमरीकी सांसदों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है जैसा कि सिर्फ मुट्ठीभर विदेशी नेताओं के साथ किया जाता है।

यह आधिकारिक राजकीय दौरा एक ऐसे वक्त पर हो रहा है। जब अपनी चौधराहट के तहत एक एक–ध्रुवीय विश्व की स्थापना करने का अमरीकी अभियान का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध बढ़ रहा है। चीन, रूस, हिन्दोस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, सऊदी अरब, केन्या, ईरान और इंडोनेशिया सहित कई देश अमरीकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के समझौतों पर काम कर रहे हैं।

नाना प्रकार के अमरीकी दबावों के बावजूद, हिन्दोस्तान ने यूक्रेन में युद्ध के संबंध में किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने से इनकार किया है। रूस पर अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद हिन्दोस्तान ने रूसी तेल के आयात में काफी वृद्धि की है।

ऐसी परिस्थिति में, हिन्दोस्तान के सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिये और यहां एक सैन्य–औद्योगिक परिसर विकसित करने के लिए, अमरीका अपनी सर्वोच्च तकनीक उपलब्ध कराने की पेशकश करके, हिन्दोस्तानी शासक वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहा है। अमरीका के रक्षा सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया है। ये दौरे इसीलिये किये जा रहे हैं ताकि हिन्दोस्तानी प्रधानमंत्री के आगामी अमरीकी दौरे के बीच कुछ महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग सौदों की घोषणा की जा सके।

अमरीकी साम्राज्यवादी एशिया में भी वही करना चाहते हैं जिसकी कोशिश वे यूरोप में कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग उकसा कर उनकी कोशिश, रूस को और साथ में यूरोपीय संघ को कमजोर करने की है। इसी तरह, वे चाहते हैं कि एशिया के देश एक दूसरे के साथ जंग करके अपने आप को बर्बाद कर दें ताकि इस महाद्वीप में भी अमरीकी चौधराहट स्थापित की जा सके।

हिन्द–प्रशांत क्षेत्र पर हावी होने की अमरीकी रणनीति में वह हिन्दोस्तान को एक सांझेदार के रूप में आकर्षित करने का इच्छुक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दुनिया की आधी से अधिक आबादी बसी हुई है और दुनियाभर में होने वाले उत्पादन का यहां दो तिहाई उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में अपनी चौधराहट जमाने के लक्ष्य को हासिल करने में अमरीका चीन को मुख्य रुकावट मानता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिये वह हिन्दोस्तान को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखता है।

हिन्दोस्तानी शासक वर्ग के अपने साम्राज्यवादी लक्ष्य हैं। हिन्दोस्तान का चीन के साथ सीमा विवाद है। चीन के साथ अपनी होड़ में अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपति अमरीकी सहायता का इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं। वे आशा कर रहे हैं कि दुनिया के कारखाने बतौर चीन का स्थान हिन्दोस्तान ले लेगा। दुनियाभर में अपनी चौधराहट जमाने के अपने रणनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये, अमरीका हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों के साम्राज्यवादी मंसूबों और चीन के साथ उनके अंतर्विरोधों का फ़ायदा उठा रहा है।

जबकि रूस अभी भी हिन्दोस्तान के रक्षा संबंधी आयातों का प्रमुख स्रोत है, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में हिन्दोस्तान का अमरीका के साथ सहयोग बढ़ रहा है। 2016 में, अमरीका ने हिन्दोस्तान को एक प्रमुख रक्षा सांझेदार का दर्ज़ा दिया था। इसके तहत, अमरीका ने हिन्दोस्तान के सशस्त्र बलों को कुछ परिष्कृत हथियार प्रणालियां उपलब्ध कराईं, जो पहले सिर्फ उसके नाटो सहयोगियों को ही उपलब्ध करायी जाती थीं। तब से हिन्दोस्तान ने अमरीका के साथ चार बुनियादी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते अमरीकी सशस्त्र बलों के लिए हिन्दोस्तान में ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। वे दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार प्रणालियों को एकीकृत करते हैं।

हिन्दोस्तान की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की सैनिक तैनाती के बारे में अमरीका हिन्दोस्तान को निगरानी की जानकारी देता है। अमरीकी सेना की हिन्द–प्रशांत कमांड ने नई दिल्ली में एक केंद्र स्थापित किया है जो चुनी हुई सरकार को नज़र अंदाज करते हुए भी, सीधे हिन्दोस्तान सैन्य बलों से समायोजन कर सकता है।

अमरीकी साम्राज्यवादी एशिया में भी वही करना चाहते हैं जिसकी कोशिश वे यूरोप में कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग

शेष पृष्ठ 3 पर

दिल्ली में पार्टी इलाका कमेटी की गोष्ठी :

यौन शोषण के ख़िलाफ़ महिला खिलाड़ियों के आंदोलन का महत्व

नई दिल्ली में 11 जून, 2023 को उपरोक्त विषय पर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की दिल्ली इलाका कमेटी ने गोष्ठी आयोजित की। इस गोष्ठी में मज़दूरों, महिलाओं और नौजवानों ने हिस्सा लिया।

सभा को संबोधित करते हुए, पार्टी के प्रवक्ता ने महिला खिलाड़ियों के जनवरी 2023 में जंतर–मंतर पर आने से पहले, उनके साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष द्वारा किए जा रहे दुराचार के बारे में खेल प्राधिकार से जुड़े कोच/अधिकारियों के ज़रिए शिकायत दिए जाने से लेकर, 28 मई को धरना स्थल से हटाए जाने तक होने वाली गतिविधियों का विवरण दिया।

उन्होंने कहा कि हमारा पूंजीवादी समाज महिलाओं के बारे में एक पिछड़ी सोच रखता है। इस समाज में एक महिला द्वारा उसके साथ हुए दुराचार की बात को सार्वजनिक रूप से कहने पर उसे 'कुलटा', 'चरित्रहीन' करार दिया जाता है। उसके परिवार का जीना हराम कर दिया जाता है। ऐसी अधिकांश महिलायें अपने साथ हुए दुराचार को लेकर चुप रहती हैं या अपनी जीवन–लीला ही समाप्त कर देती हैं।

देश की महिला खिलाड़ियों ने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने, देश के भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, जो कि एक सांसद भी है, उसके द्वारा किए जा रहे यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ को बुलंद किया। महिला खिलाड़ियों का यह क़दम, एक बहादुराना क़दम है। ये खिलाड़ी महिलाएं सराहना व आदर के योग्य हैं।

28 मई, 2023 को प्रदर्शन स्थल से महिला पहलवानों को गिरफ़्तार करते हुए (फाइल फोटो)

हमारे जैसी राजनीतिक ताक़तों के द्वारा, इन महिला खिलाड़ियों के समर्थन में खड़े होने के बावजूद, यदि वे अपने संघर्ष में सफल नहीं हो पाती हैं या संघर्ष से क़दम पीछे खींच लेती हैं, तब भी इनकी बहादुरी कमतर नहीं होती है।

महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने कई जहरीले प्रचार किए जैसे कि – ये महिलायें एक परिवार से हैं, उन्हें राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है या इनके पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं, वे जाति विशेष ख़ासकर उच्च जाति की महिलाएं हैं, वे हरियाणा की हैं, उनका समर्थन जाति विशेष के लोग कर रहे हैं, आदि, आदि। इस तरह से मौजूदा सरकार ने यौन शोषण के ख़िलाफ़ महिला पहलवानों के आंदोलन पर बहुत ही घटिया और तंग नज़रिये वाले आरोप लगाये, ताकि आंदोलन के असर को कम किया जा सके और संघर्षरत महिला खिलाड़ियों का मनोबल गिराया जा सके।

हमारा मानना है कि यौन शोषण के ख़िलाफ़ होने वाला संघर्ष, न्याय का संघर्ष है। इसमें उन सभी को अपना योगदान देना चाहिए, जो समाज में महिलाओं को लेकर एक प्रगतिशील सोच रखते हैं।

हमें याद होगा, जब जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था तो राज्य मशीनरी ने कश्मीरी लड़कियों के बारे में बहुत ही घटिया प्रचार को बढ़ावा दिया था कि 'धारा 370 के हट जाने से कश्मीरी लड़कियों के साथ

शेष पृष्ठ 2 पर

अंदर पढ़ें

- हिन्द–अमरीकी साझेदारी पर इलाका कमेटी की गोष्ठी — 2
- 'मज़दूर वर्ग आंदोलन के सामने चुनौतियां — 3
- बिजली ख़रीद समझौते पूंजीपतियों के हित में — 4
- रूस के ख़िलाफ़ लगाये गये प्रतिबंधों में स्विफ्ट की भूमिका — 5
- पाठकों की प्रतिक्रिया — 5

दिल्ली में पार्टी इलाका कमेटी की गोष्ठी :

हिन्द–अमरीकी साझेदारी लोगों के हित में नहीं

25 जून, 2023 को उपरोक्त विषय पर कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की इलाका कमेटी ने नई दिल्ली में एक गोष्ठी का आयोजन किया।

गोष्ठी में मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों ने गर्मजोशी से हिस्सा लिया। पार्टी के प्रवक्ता ने गोष्ठी का संचालन किया और पार्टी की ओर से एक प्रस्तुति की गई।

प्रस्तुति में कहा गया कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमरीकी राज्य के ख़ास अतिथि थे। प्रधानमंत्री ने 21 से 23 जून, 2023 के बीच अमरीका की यात्रा की और वहां के सांसदों को संबोधित भी किया। हमारे देश के हुक्मरान पूंजीपति वर्ग के मीडिया संस्थानों ने ढोल बजाकर इस घटना को तथाकथित महान घटना के रूप में पेश किया।

हिन्दोस्तान के हुक्मरान पूंजीपति वर्ग के मंसूबों को जाहिर करते हुए, प्रधानमंत्री ने अमरीका दौरे से पहले दिये गये अपने एक इंटरव्यू में कहा कि "विश्व स्तर पर भारत ज्यादा बड़ी और अहम भूमिका पाने का हक़दार है। भारत किसी देश की जगह नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें विश्व स्तर पर सही पोजिशन" चाहिए।

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुये, जिनमें शामिल हैं युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का संयुक्त रूप से निर्माण किया जाना तथा हिन्दोस्तान के द्वारा कई युद्धक हथियारों की ख़रीद। अमरीका हिन्दोस्तानी की नौसेना को 24,600 करोड़ रुपये की कुल क़ीमत के 31 एम.क्यू. 9–बी. ड्रोन हवाई जहाज बेचेगा। यह धन देश के मज़दूरों और किसानों से वसूला जायेगा। इसका बेशुमार मुनाफ़ा अमरीकी कंपनियों को मिलेगा। अमरीकी माइक्रोन कंपनी हिन्दोस्तान में चिप उत्पादन के लिये 22,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह कंपनी मेमोरी चिप बनाएगी।

दुनिया में चीन आर्थिक तौर पर उभर रहा है। अमरीका की हमेशा कोशिश रही है कि चीन को आगे बढ़ने से रोका जाए। इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए वह हमारे देश को मोहरा बनाना चाहता है। लंबे समय से अमरीका चीन के आस–पास के देशों को उसके ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश करता आया है। अमरीका की कोशिश रहती है कि हिन्दोस्तान और चीन में जंग हो।

अमरीकी साम्राज्यवाद एशिया में भी वही करना चाहता है जिसकी कोशिश वह यूरोप में कर रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद की कोशिश रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जंग को उकसा कर, वह रूस को और साथ साथ ही साथ यूरोपीय संघ को भी कमज़ोर करे। इसी तरह, वह चाहता है कि एशिया के देश भी एक दूसरे के साथ जंग में खुद को बर्बाद कर दें ताकि इस महाद्वीप में भी अमरीकी चौधराहट स्थापित की जा सके।

इन दिनों हिन्दोस्तान व अमरीकी हुक्मरानों के बीच आपसी अंतर्विरोध देखने को मिले हैं। अमरीका ने 2002 के गुजरात के क़त्लेआम के संबंध में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के ख़िलाफ़ बी.बी.सी. की डाक्यूमेंटरी रिलीज़ की, जिसके जवाब में हमारे देश के हुक्मरान वर्ग ने बी.बी.सी. के ऑफिस पर छापा मारा। उसी तरह से अमरीका ने पूंजीपति अडानी के ख़िलाफ़ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा किया, लेकिन देश के हुक्मरान वर्ग अमरीका के सामने नहीं झुका। उसी तरह से अमरीका के न चाहने पर भी हिन्दोस्तान रूस से तेल और हथियार ख़रीदते आया है। यूक्रेन–रूस युद्ध में, रूस की निंदा करने की अमरीका की चाहत से हिन्दोस्तान इनकार करता आया है।

हमें याद रखना चाहिए कि बेशक, पूंजीवादी देशों के बीच, साम्राज्यवादी मंसूबों के साथ, एक दूसरे के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ने की होड़ होती है लेकिन वे मज़दूर वर्ग की अगुवाई में होने वाले क्रांति की किसी भी संभावना को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह एकजुट हैं। साम्राज्यवादी अमरीका का पहला मक़सद है समाजवादी क्रांति को रोकना जिसके लिये वह अलग–अलग तरीक़े इस्तेमाल करता रहा है। इस्लामिक आतंकवाद फैलाना, जंग करना, नये–नये

शेष पृष्ठ 6 पर

यौन शोषण के ख़िलाफ़ ...

पृष्ठ 1 का शेष

शादी का रास्ता खुल गया है!' धारा 370 को कश्मीर की महिलाओं के साथ जोड़कर घटिया प्रचार करना, घटिया हरक़तों को बढ़ावा देना है। इस प्रचार पर विराम तब लगा, जब समाज में प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों के साथ–साथ देशभर के सिख गुरुद्वारों ने कश्मीरी लड़कियों की हिफ़ाज़त में आगे आने का ऐलान किया।

लड़की/महिला, वह कहीं की हो – कश्मीरी हो, पंजाबी हो, ब्रिटेन की हो या अफ्रीकी की, देश की हो या विदेश की, अमीर हो, गरीब हो या वह किसी जाति या धर्म विशेष की हो, ... उसका व उसके अधिकारों का आदर करना चाहिए। समाज में महिलाओं का दर्ज़ा पुरुषों से एक दर्ज़ा इसलिए आगे है, क्योंकि वे समाज की नयी पीढ़ी को जन्म देती हैं। अतः उसके ख़िलाफ़ होने वाले अपराध के लिए चलने वाले संघर्ष में शामिल होना, प्रत्येक न्याय पसंद और प्रगतिशील व्यक्ति का कर्तव्य है। बेशक, इस संघर्ष में शामिल होने वाला व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से जुड़ा ही क्यों न हो। पीड़िता के संघर्ष का समर्थक उसके परिवार, गांव समाज, जाति, क्षेत्र का ही क्यों न हो।

हम देख सकते हैं कि महिला खिलाड़ियों के समर्थन में कितने जाने–माने लोग आगे आए! उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं! कितने खिलाड़ी आगे आए? कितने अभिनेता आगे आए? कितने उद्योगपति आगे आए? किस–किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने इनका समर्थन किया?

समाज को प्रगतिशील होने में पूंजीवादी समाज एक बड़ी रुकावट है। यह ऐसा समाज है, जहां समाज के हित से ज्यादा, निजी हित को देखा जाता है। यहां समाज के फ़ायदे की जगह, निजी फ़ायदे को बढ़ावा दिया जाता है। समूह की जगह व्यक्ति और समाज की जगह व्यक्तिवाद हावी है। व्यक्तिगत मुनाफ़ा/हित/फ़ायदा सर्वोपरि है। खिलाड़ी बोलेंगे तो संभव है कि उन्हें भविष्य में होने वाले टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने से रोक दिया जाए, उनकी मेडल जीतने की संभावना ख़त्म हो जाए। आंदोलन में हिस्सा लेने से छात्र डरेगा कि उन्हें भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए 'अयोग्य' करार दिया जा सकता है। कलाकार बोलेगा तो आने वाले दिनों में, उसे किसी कंपनी में ब्रांड एम्बेसेडर बनने में या सरकारी एड में उसकी भूमिका मिलने की संभावना जीरो हो जाएगी। यहां तक कि एक ग़रीब आदमी को न्याय दिलाने के संघर्ष में एक साधारण सा ग़रीब आदमी आगे नहीं आता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका राशन कार्ड रद्द न हो जाए ...।

ऐसे में, महिला खिलाड़ियों ने खेल जगत में एक दुराचारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर एक बहादुरी भरा काम किया है, जो पूरे समाज के हित में है। उन्होंने कुश्ती के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाने, टूर्नामेंट में भाग लेकर मेडल जीतने की संभावना आदि को दांव पर लगा दिया है।

क्या अदालतें इंसाफ देती हैं। बिल्किस बानो का मामला हमारे सामने है। 2002 के सांप्रदायिक हत्याकांड के दौरान, उनके साथ बलात्कार किया गया और उनके परिवार के सात सदस्यों को मार डाला गया। ऐसे अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया गया। ऊपर से उनके सम्मान में सभा रखी गयी।

महिला अधिकारों को लेकर काम करने वाले प्रगतिशील महिला संगठनों ने कार्यस्थल पर यौन शोषण पर रोक लगाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष के बाद, हर एक कार्यस्थल पर कमेटी बनाने के लिए सरकार बाध्य हुई। लेकिन देखा जा रहा है कि कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो पीड़ित है, उसी पर दोष डाल दिया जाता है, उसके साथ होने वाले अत्याचार के लिए उसे ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। कार्यस्थल, संस्थान या फेडरेशन बदनाम न हो, इस बहाने मामले को रफ़ा–दफ़ा कर दिया जाता है।

महिलाओं के यौन शोषण का अपराधी हो या महिलाओं को समान काम के बदले समान वेतन न देने का अपराधी हो, दोनों ही तरह के अपराधी बच जाते हैं। महिलाओं के प्रति शारीरिक हिंसा, छेड़छाड़ सहित उनके अधिकारों को नकारे जाने की प्रवृति हमारे समाज में स्थायी समस्या बनी हुई है।

हमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा या उनके अधिकारों के हनन पर चलने वाले हर आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। ऐसे आंदोलन समाज को प्रगति की ओर ले जाने वाले क़दम हैं। इस आंदोलन में शामिल होकर इस तथ्य को उजागर करना चाहिए कि मौजूदा पूंजीवादी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ–साथ सामंतवादी तत्व महिलाओं के शोषण के लिए ज़िम्मेदार हैं। शासक वर्ग, पूंजीपति वर्ग की अगुवाई वाली व्यवस्था मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के शोषण के लिए ज़िम्मेदार हैं। हमें मौजूदा व्यवस्था की जगह मज़दूर वर्ग की अगुवाई में मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित किए जाने के आंदोलन में आगे आने का बुलावा देना चाहिए।

उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करते हुये कहा कि पहलवान एक फ़ारसी शब्द है। इसका अर्थ है, समाज में अच्छे काम में पहल की अगुवाई करने वाला। इस अर्थ में, यहां बैठे हुए सभी साथी पहलवान हैं।

इस मुख्य प्रस्तुति के बाद अन्य साथियों ने अपनी बातें रखीं।

एक नौजवान ने कहा कि हमारे देश में जब स्वर्णपदक विजेता खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जाती है, तो एक आम महिला या लड़की के साथ होने वाले अन्याय की आवाज़ को कौन सुनेगा? फिर यहां कैसी डेमोक्रेसी है? यहां कैसा संविधान है? अगर अधिकारों के लिए उठने वाली आवाज़ का दमन किया जाता है, तो यह व्यवस्था हमारे किस काम की है? हमें देशवासियों को समझाना पड़ेगा कि यह व्यवस्था लोगों के हित में काम नहीं करती है।

एक मज़दूर ने कहा कि पूंजीपति वर्ग की सरकार महिला सशक्तिकरण का दावा करती है, जबकि दूसरी ओर 4,86,000 महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। हमारे देश में अपराधी अगर सत्ता में पद पर विराजमान है तो उससे एक व्यवहार होता है। उदाहरण के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष को पोक्सो क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी का मंत्री विशेष है।

एक नौजवान ने कहा न्याय व्यवस्था इसी व्यवस्था का हिस्सा है। मज़दूरों, किसानों, महिलाओं के शोषण दमन में व्यवस्था के अन्य अंगों के साथ, न्यायालय भी ज़िम्मेदार है।

एक अन्य नौजवान ने कहा कि पहलवान महिलाओं ने खेल जगत में होने वाले यौन हिंसा के मुद्दे को उठाया है। मीडिया के ज़रिए सरकार ने इन खिलाड़ियों को ग़लत साबित करने तथा उनके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने का काम किया गया है।

एक नौजवान लड़की ने कहा कि हमारे उन मौलिक अधिकारों का क्या फ़ायदा, जब अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज उठाने पर आवाज़ को दबा दिया जाता है।

महिला अधिकारों को लेकर संघर्ष करने वाली एक कार्यकर्ता ने कहा कि महिला पहलवानों ने कार्यस्थल पर यौन शोषण को लेकर आवाज़ उठायी। हमें अवश्य उनका साथ देना चाहिए। महिलाओं के साथ हर स्तर पर शोषण होता है।

इनके अलावा, कई अन्य साथियों ने भी अपनी बातें रखीं।

गोष्ठी का समापन संचालन करने वाले साथी ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं के प्रति बहुत घटिया नज़रिया रखा जाता है। उसे एक उपभोग की वस्तु जैसा समझा जाता है। उनके साथ गैर–बराबरी का बर्ताव किया जाता है। इसके ख़िलाफ़ आगे आने वाली महिलाओं का आगे आना बहादुरी का क़दम है। हमें उनका समर्थन करना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/23703

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का

हिन्दी पाक्षिक अख़बार

मज़दूर एकता लहर

वार्षिक शुल्क 150 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये : श्री मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020

WhatsApp 09868811998

मज़दूर एकता लहर को मनीआर्डर से पैसा भेजने वाले सभी पाठकों से अनुरोध है कि पैसा भेजने के बाद हमें, इस नम्बर पर 09810167911 फ़ोन करके सूचित करें तथा एस.एम.एस. करें। ई-मनीआर्डर भेजते समय फार्म में अपना पता पूरा और साफ-साफ भरें।

हिन्दोस्तान में मज़दूर वर्ग आंदोलन के सामने चुनौतियां

कामगार एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

11 जून, 2023 को रविवार के दिन कामगार एकता कमेटी ने मुंबई में एक महत्वपूर्ण विषय "हिन्दोस्तान में मज़दूर वर्ग के आंदोलन के सामने चुनौतियां" पर एक मीटिंग आयोजित की। सभी उम्र के पुरुषों और महिलाओं, रेलवे, बिजली, रक्षा, सूचना प्राद्योगिकी, शिक्षा और गारमेंट क्षेत्र जैसे विविध व्यवसायों से आये मज़दूरों से सभागृह भरा हुआ था।

मीटिंग के प्रारंभ में, हाल ही में हुई ओडिशा रेल दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सहभागियों को याद दिलाया गया कि समय आ गया है कि एकजुट होकर सरकार और रेल अधिकारियों से कठोरता से सवाल पूछे जायें और इस व्यवस्थागत नाकामी के लिए जवाबदेही की मांग की जाये।

यह रिपोर्ट विभिन्न सहभागियों द्वारा व्यक्त किए गए मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करती है।

आवश्यकता की सभी वस्तुएं मज़दूर और किसान बनाते हैं और देश के लोगों का भरण–पोषण करते हैं। वे देश की पूरी आबादी का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। लेकिन उनकी बहुत ही सरल, बुनियादी ज़रूरतें – भोजन, पानी, स्वच्छता, आवास, कपड़े, बिजली, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं, उन्हें नहीं मिल पा रही हैं तथा उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश के क़ानून और नीतियां कैसे तय होते हैं और लागू किये जाते हैं, जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमारे संघर्षों को कुचलने के लिए शासक अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, वह पूंजीपति वर्ग के एजेंडे को लागू करती है ताकि वे हमारे ख़र्च पर अमीर होते रहें।

पूंजीवाद हमारे देश में उत्पादन का प्रमुख तरीक़ा है, जो अर्थव्यवस्था को चला रहा है। पूंजीपति उत्पादन के साधनों और वित्तीय संसाधनों को अपनी निजी संपत्ति के रूप में रखते हैं और पूरी तरह से दूसरों के श्रम पर ज़िन्दा रहते हैं। जिनमें शामिल हैं – बड़े उद्योगों, खदानों और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के मालिक, बड़े थोक व्यापारी, साहूकार, ज़मीन और भवन के मालिक और बड़े पूंजीपति किसान शामिल हैं। जिनकी कुछ संख्या दस–लाख के आस–पास है।

हिन्दोस्तान में अमरीकी डॉलर के अरबपतियों की संख्या 166 है, उन सभी की संयुक्त संपत्ति लगभग 60 लाख करोड़ रुपये (75,000 करोड़ डॉलर) है। उन 166 व्यक्तियों की कुल संपत्ति, हिन्दोस्तान की 140 करोड़ आबादी की कुल वार्षिक आय का एक चौथाई से अधिक है।

जबकि देश में 14 लाख से अधिक पंजीकृत कंपनियां हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती हैं। लगभग 150 इजारेदार समूहों की मालिकी वाली 1,000 से भी कम कंपनियां लगभग सभी बाज़ारों पर हावी हैं। अधिक से अधिक वे हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों – भोजन, बिजली, शिक्षा, परिवहन, संचार, आईटी आदि जैसी बुनियादी सेवाओं पर हावी हो जाती हैं। ये इजारेदार कंपनियां अपने मज़दूरों को कम से कम वेतन देकर, उपयोगकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं को लूटकर और मनमाना मूल्य वसूल कर उनका शोषण करती हैं।

सत्ता में चाहे कोई भी हो, पूंजीपतियों और आम लोगों के बीच की खाई और भी गहरी होती रहती है। ये कारोबारी घराने भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को हजारों करोड़ रुपये देते हैं। यही उन्हें इन पार्टियों का मालिक बनाता है। जब कोई पार्टी या पार्टियों का गठबंधन सरकार बनाता है, तो उसका काम होता है, करोड़ों रुपये देने वालों के एजेंडे को लागू करना, जबकि विपक्ष की पार्टी लोगों के हितों की रक्षा करने का ढोंग करके लोगों को मूर्ख बनाती है।

यह जाहिर है कि अगर हम पूंजीपतियों के शासन को जारी रहने देंगे तो हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। जिसका विकल्प है मज़दूर वर्ग और मेहनतकशों का शासन स्थापित करना और उनके लिए धरती पर स्वर्ग बनाना, यही कामगार एकता कमेटी का उद्देश्य है। पहला क़दम है यह पहचानना कि मज़दूर कौन है।

आय या नौकरी के प्रकार के आधार पर मज़दूर वर्ग की पहचान करना ग़लत है। जो कोई भी उत्पादन के साधनों और सेवाओं के मालिकों को अपनी श्रम शक्ति बेचकर अपनी आजीविका कमाता है, वह एक श्रमजीवी है। निचले दर्जे के कामगारों के साथ–साथ, इसमें अत्यधिक योग्य लोग जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, आईटी कर्मचारी आदि भी शामिल हैं। उत्पादन के साधनों और सेवाओं के मालिकों का एकमात्र उद्देश्य होता है लगातार अधिकतम लाभ कमाते रहना। यह केवल मज़दूरों को कम से कम संभव मज़दूरी देकर ही किया जा सकता है। मालिकों और मज़दूरों के हित, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और इन हितों को कभी भी एक साथ नहीं रखा जा सकता है।

किसानों के साथ–साथ मज़दूर एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो लोगों के जीवन और भलाई के लिए आवश्यक है। आज पूंजीपति, ख़ासकर बड़े–बड़े कॉर्पोरेट घराने बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और किसानों और मज़दूर वर्ग को बर्बाद कर रहे हैं। पूंजीपति वर्ग मज़दूरों और किसानों दोनों का साझा दुश्मन है। मज़दूरों और किसानों, दोनों के लिए यह आवश्यक है कि वे इसे पहचानें और पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ एकजुट हों।

पूंजीपति वर्ग यह अच्छी तरह जानता है कि अपने शासन को बनाए रखने के सबसे विश्वसनीय तरीक़ों में से एक है – "फूट डालो और राज करो" – की ब्रिटिश नीति, जिसको इसने और भी विकसित किया है। हम हर दिन अपने देश के मज़दूरों और मेहनतकशों को उनके धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर विभाजित होते और निशाना बनते देखते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह हमला सिर्फ़ उस समुदाय विशेष पर नहीं है, बल्कि यह पूरे मज़दूर वर्ग पर हमला है!

पूंजीपति वर्ग भी मज़दूरों का यूनियन और गैर यूनियन, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता तथा पार्टी संबद्धता के आधार पर विभाजित करता है। उसी तरह से मज़दूर जो शारीरिक श्रम करते हैं और बौद्धिक कार्य करते हैं (जिन्हें यहां तक कि मज़दूर भी नहीं माना जाता है) या इसके अलावा, स्थाई और अनुबंधित मज़दूरों के बीच या कर्मचारियों और सुपरवाइजर के बीच विभाजित करता है।

हिन्दोस्तानियों में एकमात्र विभाजन है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और वह है वर्ग विभाजन। पूंजीपति वर्ग और मज़दूरों व मेहनतकशों के हित बिल्कुल विपरीत हैं और इनमें कभी भी तालमेल नहीं हो सकता। हमारी प्राथमिक पहचान मज़दूर वर्ग के सदस्य बतौर होनी चाहिए। हमारी प्राथमिक निष्ठा मज़दूर वर्ग के प्रति होनी चाहिए।

पितृसत्ता को जीवित रखने वाली इस पूंजीवादी व्यवस्था में महिलाओं का दोहरा शोषण किया जाता है, मज़दूर के रूप में भी और महिलाओं के रूप में भी। यदि महिलायें जागृत और संगठित हों तो वे हमारे वर्ग की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगी। इसी तरह नौजवानों में भी क्रांतिकारी क्षमता है। उनके पास असीम ऊर्जा और आशावाद है और वे नए विचारों के साथ प्यार करते हैं। ऐतिहासिक रूप से पूरे विश्व में महिलाओं और नौजवानों ने मानवता की प्रगति में एक बड़ी भूमिका निभाई है। महिलाओं के साथ–साथ नौजवानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये, मज़दूर संगठनों को विशेष प्रयास करने चाहिएं और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए।

अगर हम वर्ग के रूप में एकजुट हो जाएं तो हम अपने ऊपर बढ़ते हमलों को नाकाम कर सकते हैं। जबकि ऐसा करना महत्वपूर्ण है, हमारे रणनीतिक लक्ष्य को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। हमें संगठित होकर किसानों और अन्य मेहनतकशों के साथ मिलकर अपने देश का शासक बनना है।

हमें अपने वर्ग के भाइयों और बहनों को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम शासन करने में सक्षम हैं, क्योंकि उनमें से एक बड़ी संख्या अपने वर्ग की ताक़त को कम आंकती है। एक शासक का प्राथमिक कर्तव्य है, उन सभी की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना, जो मेहनत करके समाज में योगदान करते हैं। आज के शासक इसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं।

यह हम ही हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ मानव निर्मित आपदाओं और हड़बड़ी में लगाये गये लॉकडाउन तथा राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक "दंगों" से अपने अनगिनत साथी नागरिकों को बचाते हैं। एक साल तक चलने वाला किसान आंदोलन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसने किस तरह से लोगों की ज़रूरतों के साथ–साथ उनकी सुरक्षा का ध्यान भी बहुत ही संगठित तरीक़े से रखा गया।

हमने समय–समय पर अपनी इच्छा और हमारे पास मौजूद अल्प संसाधनों के साथ ऐसा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। आज देश के संसाधनों को नियंत्रित करने वाले अरबपतियों के बजाय अगर हम देश के संसाधनों को नियंत्रित करेंगे, तो हम इस धरती पर स्वर्ग बना पाएंगे।

2024 के चुनाव की तैयारी में अलग–अलग पार्टियों ने अभी से हमें रिझाना शुरू कर दिया है। हमें इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि 2024 में सत्ता में आने वाली यह या वह पार्टी हमारी समस्याओं को हल करने वाली है। इसलिये मज़दूर वर्ग के स्वतंत्र कार्यक्रम को विकसित करने और एकजुट करने के लिए यथासंभव व्यापक चर्चा करें : अर्थव्यवस्था को सभी मेहनतकशों की निरन्तर बढ़ती हुई भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनकी अधिकतम भलाई करने की ओर उन्मुख होना चाहिए। किसी के शोषण या दमन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए; अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के पास होनी चाहिए और निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए; दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के लोगों के साथ आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाने चाहिए।

हमें अपने संगठनों को गुणात्मक रूप से और संख्या की दृष्टि से मजबूत करके अपनी लड़ने की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। हमें एकजुट होकर मज़दूर वर्ग और अन्य मेहनतकशों के एजेंडे को केंद्र में लाना होगा! हमें अपने देश का शासक बनने के लिए संगठित होना होगा।

http://hindi.cgpi.org/23708

हिन्द–अमरीकी साझेदारी हिन्दोस्तानी लोगों के हित में नहीं है

पृष्ठ 1 का शेष

उकसा कर उनकी कोशिश, रूस को और साथ में यूरोपीय संघ को कमजोर करने की है। इसी तरह, वे चाहते हैं कि एशिया के देश एक दूसरे के साथ जंग करके अपने आप को बर्बाद कर दें ताकि इस महाद्वीप में भी अमरीकी चौधराहट स्थापित की जा सके।

हम कभी नहीं भूल सकते कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात राज्यों के बीच स्थापित किये हर एक नियम व मानक का उल्लंघन अमरीका द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करने में अमरीका का सबसे लंबा इतिहास है। उसने कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, चिली, एल सलवाडोर, लेबनॉन, ग्रेनाडा, पनामा और यूगोस्लविया सहित अनेक देशों में हमला किया है और कब्ज़ा जमाया है। इस शताब्दी में, एक देश के बाद दूसरे में तबाहकारी जंग का बोझ अमरीकी साम्राज्यवाद ने दुनिया पर लादा है। ऐसे देशों की सूची में अफ़ग़ानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया और यूक्रेन शामिल हैं।

दुनिया में शांति को सबसे बड़ा ख़तरा अमरीकी साम्राज्यवाद से और दुनियाभर में उसके द्वारा अपनी चौधराहट जमाने से जारी है। एशिया में उसकी योजना हिन्दोस्तानी लोगों के लिये और इस महाद्वीप के दूसरे देशों के लिये ख़तरनाक और उनके लिये नुक़सानदायक है।

अमरीकी साम्राज्यवादी हिन्दोस्तान के लिये कभी भी भरोसेमंद मित्र नहीं हो सकता है। उसका लक्ष्य है एशिया और पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट स्थापित करने की अपनी अपराधिक जंगी योजना में हिन्दोस्तानी लोगों को तोप के चारे की तरह इस्तेमाल करना।

अमरीकी साम्राज्यवाद और चौधराहट जमाने की उसके अभियान के ख़िलाफ़ अपने देश में मज़दूर वर्ग और लोगों की एकता बनाई जा सकती है और बनानी होगी। रक्षा और खुफ़िया जानकारी के लिये हिन्द–अमरीकी गठबंधन को मजबूत करने के हिन्दोस्तानी शासक वर्ग के हरेक क़दम का हमें विरोध करना चाहिये।

http://hindi.cgpi.org/23706

बिजली ख़रीद समझौते इजारेदार पूंजीपतियों के हित में

बिजली आज के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अन्य आवश्यकताओं के साथ–साथ, इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों के लिए ऐसी क़ीमत पर करवाये, जो लोगों की ख़रीद क्षमता के भीतर हो। राज्य ने न केवल इस ज़िम्मेदारी को निभाने से इंकार किया है बल्कि बिजली को इजारेदार पूंजीपतियों की मुनाफ़ाख़ोरी की वस्तु में बदल दिया है।

बिजली मूल्य निर्धारण की नीति को निजी बिजली उत्पादक इजारेदार पूंजीपति, अपने हित में निर्देशित कर रहे हैं। आज टाटा, अदानी और अन्य इजारेदारों के बिजली संयंत्र आयात किये जाने वाले कोयले के इस्तेमाल से चलते हैं। भारतीय ऊर्जा विनिमय के माध्यम से उनके द्वारा बेची जाने वाली बिजली की क़ीमत, 20 रुपये प्रति यूनिट तक चार्ज करने की उन्हें अनुमति है!

एक वितरण कंपनी किसी उत्पादक कंपनी से जिस क़ीमत पर बिजली ख़रीदती है, वह लोगों द्वारा भुगतान की गई दर का 70–80 प्रतिशत होती है। इस दर का बाक़ी हिस्सा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े ख़र्चे होते हैं। इसलिए, उत्पादक कंपनियां जिन क़ीमतों पर बिजली बेचती हैं, उनके आधार पर ही लोगों को बेची जाने वाली बिजली के दरें निर्धारित होती हैं।

बिजली उत्पादक निजी कंपनियां, राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ बिजली ख़रीद समझौता (पी.पी.ए.) करती हैं। ऐसे बिजली ख़रीद समझौते, उन्हें एक सुनिश्चित बाज़ार और एक ऐसी क़ीमत पर बिजली बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं, जो अधिकतम मुनाफ़े की गारंटी देता है।

1992 में जब बिजली उत्पादन को लाइसेंस मुक्त किया गया था और निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। उसके बाद बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए पूंजीपतियों के बीच होड़ लग गयी थी, क्योंकि उन्हें दीर्घकालीन बिजली ख़रीद समझौतों के ज़रिये आकर्षक मुनाफ़े सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया था। पूंजीपतियों ने नई नीति की घोषणा के दो साल के भीतर ही बिजली परियोजनाओं के लिए 130 से ज्यादा समझौते किए। इन परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता, उस समय देश में स्थापित बिजली उत्पादन की क्षमता से अधिक थी!

एक निश्चित मात्रा में बिजली की ख़रीद के लिए, डिस्कॉम द्वारा 25 साल तक की लंबी अवधि के लिए बिजली ख़रीद समझौते किए जाते हैं। इसके लिए राज्य विद्युत बोर्डों को अगले 25 सालों में होने वाली बिजली की मांग का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादनकर्ता के साथ किये गये बिजली ख़रीद समझौते को जायज़ ठहराने के लिए, बिजली की अनुमानित मांग को अधिक आंकने के लिए डिस्कॉम को मजबूर होना पड़ा है। नतीजतन, डिस्कॉम अपनी आवश्यकताओं से कहीं अधिक बिजली ख़रीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई राज्यों में तो अनुबंधित क्षमता बिजली की अधिकतम मांग से कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र ने 37,896 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली ख़रीद समझौते किये थे, जबकि इसकी अधिकतम मांग केवल 22,516 मेगावाट थी यानि कि अधिकतम आवश्यकता का लगभग 1.7 गुना अधिक। इसी तरह तमिलनाडु में जब अधिकतम मांग केवल 14,223 मेगावाट थी, तब भी बिजली बोर्ड ने 26,975 मेगावाट बिजली की ख़रीद के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि अधिकतम मांग से लगभग 90 प्रतिशत से अधिक है।

बिजली ख़रीद समझौता प्रणाली टाटा, अडानी, जिंदल, टोरेंट, आदि जैसे इजारेदार पूंजीपतियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है। कुल मिलाकर उनका हिस्सा देश की उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक है।

डिस्कॉम द्वारा उत्पादन संयंत्र को बिजली के लिये भुगतान की जाने वाली दर के दो हिस्से होते हैं – एक निश्चित हिस्सा और एक परिवर्तनीय हिस्सा। डिस्कॉम को उत्पादक कंपनी से बिजली न लेने पर भी निश्चित हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। जिसे 'निष्क्रिय क्षमता शुल्क' के रूप में जाना जाता है। इस तरह से डिस्कॉम को बिजली ख़रीदे बिना ही एक निजी बिजली उत्पादक कंपनी को, इस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। यह निष्क्रिय क्षमता शुल्क पुराने उत्पादन संयंत्रों के लिए औसतन लगभग 2 रुपये प्रति यूनिट होता है।

मध्य प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों ने 2016–17 से 2020–21 के दौरान, निजी उत्पादन कंपनियों से बिजली प्राप्त किए बिना ही 'निष्क्रिय क्षमता शुल्क' के रूप में 2,834 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। अंततः डिस्कॉम इस अतिरिक्त लागत का बोझ बिजली की बढ़ी हुई दरों के ज़रिये लोगों पर ही डाल देते हैं।

मूल्य का परिवर्तनीय हिस्सा यह सुनिश्चित करता है कि ईंधन और अन्य उत्पादन लागत में किसी भी वृद्धि को पूरी तरह से वसूल किया जाये और जिसका भुगतान अंततः लोगों द्वारा ही किया जाता है।

इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा जब चाहे पी.पी.ए. का उल्लंघन

इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा बिजली ख़रीद समझौते का उल्लंघन तब किया जाता है, जब ये समझौते किसी भी कारण से उनके मुनाफ़े के प्रतिकूल हो जाते हैं। हालांकि, पूंजीपतियों का कहना है कि बिजली ख़रीद समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही ये समझौते डिस्कॉम और अंततः उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक प्रतिकूल हो जाएं।

आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2019 में अनुमान लगाया था कि बिजली ख़रीद समझौते के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान, उसने सालाना 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया था। ये बिजली ख़रीद समझौते, सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के साथ किये गये थे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान तकनीकी विकास के कारण सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न की जाने वाली बिजली की लागत में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। हस्ताक्षरित किये गये बिजली ख़रीद समझौते में बिजली की दर ज्यादा थी, जबकि इस समय सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली बहुत कम दरों पर उपलब्ध है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश सरकार, राज्य में बिजली की दरों को कम करने के लिए बिजली ख़रीद समझौतों पर फिर से बातचीत करना चाहती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि वह इन समझौतों की दोबारा समीक्षा नहीं कर सकती है और न ही उन पर फिर से बातचीत कर सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा कि "बिजली ख़रीद समझौते 'सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी अनुबंध' हैं। यदि अनुबंधों का सम्मान नहीं किया जाता है तो निवेश आना बंद हो जाएगा। उपरोक्त कारणों से सभी समझौतों को रद्द करना ग़लत है और क़ानून के ख़िलाफ़ होगा।"

दूसरी ओर, जब इजारेदार पूंजीपति बिजली ख़रीद समझौते का उल्लंघन करना चाहते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 'सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी अनुबंध' नहीं माना जाता। टाटा और अदानी समूह की कंपनियों द्वारा आयातित कोयले की क़ीमत में वृद्धि के बाद बिजली की क़ीमतों में संशोधन करने की मांग की गई और उन्हें अनुमति दी गई। हाल ही में, जब यूक्रेन में युद्ध के कारण कोयले की क़ीमतें बढ़ गईं, तो इन संयंत्रों ने अपने समझौतों का सम्मान करने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए अपने संयंत्रों को बंद कर दिया कि बिजली के लिये उन्हें दी जा रही क़ीमत उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूर्ण उत्पादन तभी शुरू किया जब उन्हें एनर्जी एक्सचेंज में 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचने की अनुमति दी गई!

अदानी पावर ने गुजरात में मुंद्रा तट पर, पूरी तरह से आयातित कोयले से चलने वाले एक बिजली संयंत्र को स्थापित किया। उसने 2.35 से 2.89 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली की आपूर्ति के लिए 25 साल लंबा समझौता किया। लेकिन 2011 में जब आयातित कोयले की क़ीमत में उछाल आया, तो उसने बिजली ख़रीद समझौता होने के बावजूद, यह घोषणा कर दी कि वह क़ीमत में संशोधन होने पर ही बिजली की सहमत मात्रा की आपूर्ति करने के अपने समझौते को पूरा कर सकता है। राज्य और केंद्र सरकार ने इस मांग पर सहमति जताई। अदानी पावर और सरकार के बीच दिसंबर 2018 में एक पूरक–समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

राज्य विधानसभा में गुजरात के ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, अदानी पावर से ख़रीदी गई बिजली की औसत लागत दोगुनी से अधिक हो गयी – 2021 में यह 3.58 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 2022 में 7.24 रुपये प्रति यूनिट हो गई। बिजली की क़ीमतों में उछाल के बावजूद, राज्य सरकार ने 2021 की तुलना में 2022 में अदानी पावर से 7.5 प्रतिशत ज्यादा बिजली की ख़रीदारी की।

इस प्रकार, मूल्य और मात्रा के संबंध में निजी इजारेदार बिजली उत्पादक कंपनियों द्वारा बिजली ख़रीद समझौते का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम को अनुबंधित क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में इसे बनाए रखने के लिए मजबूर किया जाता है।

इजारेदार पूंजीपतियों को अधिक से अधिक मुनाफ़े की गारंटी

केंद्र सरकार द्वारा, विद्युत नियामक आयोगों को "लागत प्लस लाभ" के आधार पर 'लाभदायक' बिजली टैरिफ तय करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। टैरिफ निर्धारण के लिए, इस समय मुनाफ़े की गारंटीकृत दर थर्मल पावर के लिए 15.5 प्रतिशत है और पवन व सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों के लिए 16 प्रतिशत है। यह इक्विटी पर टैक्स के बाद का रिटर्न है। निजी बिजली उत्पादकों के लिए मुनाफ़े की गारंटीकृत दर, अन्य क्षेत्रों में हिन्दोस्तान के उद्योगों के लाभ की औसत दर से बहुत अधिक है। बिजली उत्पादन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक होने का दावा करके, मुनाफ़े की ऊंची दर को उचित ठहराया जाता है।

पिछले कुछ सालों के दौरान, बिजली उत्पादकों का ध्यान अक्षय ऊर्जा के उपयोग की ओर स्थानांतरित हो गया है – मुख्य रूप से सौर व पवन ऊर्जा की ओर। इजारेदार पूंजीपतियों को सौर ऊर्जा पर आधारित विशाल संयंत्र लगाने के लिए कर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके लिए उन्हें कौड़ियों के दाम पर या पट्टे पर ज़मीनों के बड़े हिस्से मुहैया कराए जा रहे हैं।

अक्षय–ऊर्जा का क्षेत्र पूरी तरह से निजी इजारेदार कंपनियों के प्रभुत्व में है – इस क्षेत्र में अदानी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। डिस्कॉम को न केवल अक्षय–ऊर्जा उत्पादक के साथ बिजली ख़रीद समझौते करने के लिए मजबूर किया जा रहा है बल्कि उन्हें अपनी बिजली ख़रीद में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। नतीजन, डिस्कॉम राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनियों (जेनकोज़) से कम से कम बिजली ले रहे हैं। जल्द ही अधिकांश जेनकोस बीमारू स्थिति में पहुंच जाएंगे और उनके निजीकरण को सही ठहराने के लिए उनकी इस बीमार अवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। बिजली उत्पादन पर चंद बड़े पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा, फिर वे ही देश में बिजली की दरें तय करेंगे।

बिजली ख़रीद समझौते और बिजली नीतियों का वास्तविक उद्देश्य, बिजली उत्पादन को इजारेदार पूंजीपतियों के लिए गारंटीशुदा मुनाफ़ों के साथ–साथ, एक कम जोख़िम वाला व्यवसाय बनाना रहा है। पीपीए ने राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन और वितरण कंपनियों की वित्तीय–हालातों को ख़राब कर दिया है, जिससे उनके निजीकरण के लिए ज़रूरी वजह और औचित्य के रूप में हालातें तैयार हो रही हैं।

http://hindi.cgpi.org/23700

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का प्रकाशन

यह पुस्तिका कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा 13 मई, 2018 को दिल्ली में पार्टी की एक सभा में प्रस्तुत की गई थी।

इस पुस्तिका को मंगाने के लिये संपर्क करें : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली 110020

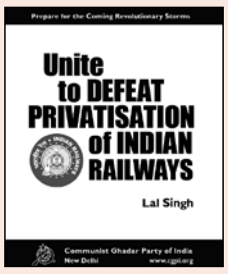

फोन : 09810167911, 9868811998, डाक खर्च सहित 40 रुपये भेजें

रूस के ख़िलाफ़ लगाये गये प्रतिबंधों में स्विफ्ट की भूमिका

शीत युद्ध की समाप्ति और दुनिया के दो–ध्रुवीय विभाजन के ख़त्म होने के बाद से, अमरीका अपने वर्चस्व के तहत एक–ध्रुवीय दुनिया की स्थापना करने की रणनीति पर आगे बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में, अमरीका इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन के लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका का उद्देश्य है रूस को घेरना और कमज़ोर करना, फ्रांस व जर्मनी को कमज़ोर करना और यूरोप में अमरीका के वर्चस्व को मजबूत करना।

रूस को कमज़ोर करने के लिए, अमरीका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की सहमति के बिना एकतरफ़ा तरीक़े से लगाया गया है। फ्रांस के वित्त मंत्री ने इन प्रतिबंधों को "सम्पूर्ण आर्थिक और वित्तीय युद्ध" के रूप में वर्णित किया है।

रूसी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने वाले प्रतिबंधों में से एक का उद्देश्य है विदेशी मुद्रा के व्यापार में, माल के आयात और निर्यात में अनेक बाधाएं डालना। इसे अंजाम देने के लिये कई सारे रूसी बैंकों को एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. – सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) – से हटा दिया गया था। स्विफ्ट तेज़ी से और सुरक्षित संदेश भेजने की प्रणाली है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा, एक देश से दूसरे देश को फंड ट्रांसफर करने के निर्देश भेजने के लिए किया जाता है। विदेशी मुद्रा के लेनदेन के लिए यह एक आवश्यक वैश्विक प्रणाली है, क्योंकि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कोई और विकल्प नहीं है।

स्विफ्ट की स्थापना 1973 में टेलेक्स के माध्यम से संदेश भेजने की पुरानी प्रथा को बदलने के लिए की गई थी और अब इसका उपयोग 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सुरक्षित संदेश और भुगतान आदेश भेजने के लिए किया जाता है। यह प्रतिदिन 4 करोड़ से अधिक संदेश भेजता है, क्योंकि कंपनियों और सरकारों के बीच रोज़ाना खरबों डॉलर का लेनदेन होता है। (स्विफ्ट के बारे में विस्तृत विवरण के लिए बॉक्स देखें)

मार्च 2022 में सात रूसी बैंकों को स्विफ्ट से हटा दिया गया, जिनमें बैंक ओत्कृति, नोविकोम्बैंक, प्रोम्सव्याजबैंक, बैंक रोसिया, सोवकोमबैंक, विनेशीकोनोमबैंक और वीटीबी बैंक शामिल हैं। जून 2022 में रूस के सबसे बड़े बैंक स्बेर बैंक सहित तीन और रूसी बैंकों को स्विफ्ट से हटा दिया गया।

स्विफ्ट से हटा दिये गए किसी भी बैंक को अन्य वित्तीय संस्थानों को धन भेजने में बहुत मुश्किल होगी और उसके ग्राहकों को अपने विदेशी मुद्रा व्यवसाय का संचालन करने में जद्दोजहद करनी पड़ेगी।

इसका उद्देश्य रूसी कंपनियों के लिए स्विफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य सुचारू और तत्काल लेनदेन की पहुंच को ख़त्म करना था, जिससे रूस के मूल्यवान ऊर्जा और कृषि निर्यात के लिए भुगतान बाधित हो जाये।

रूसी आयात और निर्यात के भुगतान में शामिल बैंकों को अब एक दूसरे के साथ सीधे लेनदेन करना होगा, जिसकी वजह से ज्यादा समय और ख़र्च लगेगा और इसके फलस्वरूप, रूसी सरकार के राजस्व में कटौती होगी।

2014 में भी रूस को स्विफ्ट से हटा देने की धमकी दी गई थी। लेकिन अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगियों ने उस समय उस धमकी पर अमल नहीं किया था। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने बड़े रूसी बैंकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था और अमरीकी क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने रूसी बैंकों के लेन–देन को रोक दिया था। इस ख़तरे ने रूस को स्विफ्ट के विकल्प के रूप में अपने स्वयं की क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली और एक सीमा–पार बैंक हस्तांतरण प्रणाली विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिसे सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाईनेन्सीअल मेसेजेस (एस.पी.एफ.एस.) कहा जाता है। 2020 तक, एस.पी.एफ.एस. में 1.3 करोड़ संदेशों का ट्रेफिक था, जबकि 400 से अधिक वित्तीय संस्थान इस प्रणाली से जुड़े थे। स्विफ्ट से निकाले जाने के प्रभाव को कम करने के लिए, रूसी सरकार वर्तमान में चीनी सरकार के साथ चीन की क्रॉस–बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (सी.आई.पी.एस.) से जुड़ने के लिए काम कर रही है, जो कि स्विफ्ट का एक अन्य विकल्प है और जो चीनी मुद्रा, युआन में भुगतान की प्रक्रिया करता है।

रूस पर वित्तीय प्रतिबंध न केवल रूस को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे जर्मनी व यूरोपीय संघ के अन्य देशों सहित हिन्दोस्तान, चीन और उन सारे दूसरे देशों को भी प्रभावित करते हैं जो रूस के साथ व्यापार करते हैं।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने 2013 में ईरान के ख़िलाफ़ इसी तरह के प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया था ताकि ईरान की सरकार पर अमरीकी वर्चस्व के सामने घुटने टेकने के लिए दबाव डाला जा सके। प्रतिबंधों के ज़रिये किसी भी देश को ईरान के साथ व्यापार करने से रोक दिया गया था और ईरानी बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग करने की इजाज़त नहीं थी।

स्विफ्ट एक 'पक्ष निरपेक्ष' संगठन होने का दावा करता है। हक़ीक़त यह है कि यह अमरीकी साम्राज्यवादियों और उसके यूरोपीय सहयोगियों के आदेश पर काम करता है। इस सच्चाई को छुपाने के लिये यह दावा किया जा रहा है कि स्विफ्ट को बेल्जियम के फ़ैसलों का पालन करना होता है, क्योंकि इसका तथाकथित मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है! पर इस सच्चाई को छिपाया जाता है, कि बेल्जियम को अमरीका और उसके प्रमुख नाटो सहयोगियों के हुक्म का पालन करना पड़ता है!

यह जाना जाता है कि अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एन.एस.ए.) हजारों बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्विफ्ट नेटवर्क के डाटा को अपने नेटवर्क में भेज देती है। इस तरह वह स्विफ्ट के माध्यम से होने वाले बैंकिंग लेनदेन और साथ ही क्रेडिट कार्ड के लेनदेन पर निगरानी रखती है।

अमरीका अपनी भारी आर्थिक और सैन्य शक्ति का उपयोग करके इस या उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में और स्विफ्ट को उन देशों के बैंकों की लेनदेन को रोकने के लिए मजबूर करने में सक्षम है। अमरीका ने नाटो पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके, नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों को अपनी लाइन पर चलने के लिए बार–बार मजबूर किया है।

http://hindi.cgpi.org/23715

स्विफ्ट के बारे में

स्विफ्ट बेल्जियम के क़ानून के तहत एक सहकारी कंपनी है और इसकी मालिकी व नियंत्रण इसके शेयरधारकों (वित्तीय संस्थानों) द्वारा किया जाता है, जो दुनियाभर के लगभग 2,400 शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेयरधारक दुनियाभर के बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 'स्वतंत्र' निदेशकों के एक बोर्ड का चुनाव करते हैं, जो कंपनी को नियंत्रित करता है और कंपनी के प्रबंधन पर निगरानी रखता है।

जी–10 (बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, अमरीका, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन) के केंद्रीय बैंकों के साथ ही साथ यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा स्विफ्ट के कामकाज पर चौकसी रखी जाती है। नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम स्विफ्ट पर प्रमुख निगरानी रखता है।

2012 में, इस ढांचे की समीक्षा की गई और स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम की स्थापना की गई, जिसमें जी–10 केंद्रीय बैंकों के अलावा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के अन्य केंद्रीय बैंकों को शामिल किया गया था। इनमें शामिल हैं रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कोरिया, बैंक ऑफ रूस, सऊदी अरेबियन मॉनेटरी एजेंसी, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, साउथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की।

स्विफ्ट को अमरीकी और यूरोपीय बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था, जो नहीं चाहते थे कि कोई भी संस्था अपनी स्वयं की प्रणाली विकसित करे और अपनी इजारेदारी स्थापित करे।

1960 के दशक के अंत में, सोसाइटी फाइनेंसिएर यूरोपिएन (एस.एफ.ई.), जो कि लक्ज़मबर्ग और पेरिस में स्थित छह प्रमुख बैंकों का एक संघ है, उसने एक 'संदेश–स्विचिंग' परियोजना शुरू की थी, जो बाद में स्विफ्ट प्रणाली में विकसित हुई।

पाठकों की प्रतिक्रिया

मणिपुर में कौन समस्या पैदा कर रहा है?

प्रिय संपादक,

इस विषय पर शानदार लेख को प्रकाशित करने के लिए बधाई। इस लेख ने मीडिया के साथ–साथ कई सोशल मीडिया चैनलों पर दिखाई देने वाले झूठ के कोहरे के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए बहुत कुछ किया है।

जैसा की इसमें साफ लिखा गया है, जो मणिपुर में पिछले दो महीनों से हो रहा है, वो किसी भी हाल में दंगे नहीं है, जहां लोग अपने आप ही हिंसा पर उतर आए। न सिर्फ सशस्त्र बल जो मणिपुर के हर हिस्से में तैनात हैं, बल्कि पुलिस को भी स्थिति को मिनटों में नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षण मिला है। इसके बावजूद, हिंसा हुई और पुलिस बस देखती रही। सब जानते हैं कि सशस्त्र बलों की तरह पुलिस को भी आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो हिंसा की अनुमति देना स्पष्ट रूप से सर्वोच्च अधिकारियों की योजना थी!

ऐसा भारत में पहले भी हुआ है। जैसा कि इस लेख ने हमें याद दिलाया है, कांग्रेस ने 1984 और भाजपा ने 2002 के नरसंहारों को आयोजित किया और उन्हें सांप्रदायिक हिंसा बताकर लोगों को गुमराह किया। वास्तव में, "दंगा" शब्द उपयोग करके शासक वर्ग ने अपने राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए अपराधों के लिए आम लोगों को दोषी ठहराने की जानबूझकर कोशिश की है।

जैसा लेख में बताया गया है, यह ध्यान रखना उचित है कि सभी समुदायों के लोग सदियों से एक साथ शांति से रहते आ रहे हैं और एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग, लोगों को बांटने और उन पर शासन करने के लिए जानबूझकर भावनाएं भड़काते हैं। लेकिन, हमेशा की तरह, मणिपुर में भी आम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे समुदाय के लोगों को बचाया है।

सबसे खुशी की बात यह है कि "ऐसे कई जिले हैं जो शांतिपूर्ण रहे हैं, जैसे कि वे क्षेत्र जहां नागा लोगों के संगठनों को व्यापक समर्थन प्राप्त है।" यदि जन संगठन, अपने कम संसाधनों के साथ, अपने क्षेत्रों को शांतिपूर्ण रख सकते हैं, तो इससे केंद्र और मणिपुर सरकारों के ख़िलाफ़ मामला और भी मजबूत हो जाता है।

मणिपुर में हिंसा के पीछे वास्तव में पूंजीपति वर्ग का शासन है। यह वर्ग मुट्ठीभर लोगों से चलता है और सत्ता में बने रहने के लिए "फूट डालो और राज करो" इस वर्ग के पसंदीदा तरीकों में से एक है।

पूर्वोत्तर और विशेष रूप से मणिपुर की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद। दशकों से कुख्यात आफ्स्पा के खिलाफ शक्तिशाली संघर्ष हुए हैं और आपने उन्हें उजागर किया है। जैसा कि आपने स्पष्ट बताया है, इस हिंसा को फैलाने का असली उद्देश्य सैन्य शासन और आफ्स्पा को जारी रखना है। शासक वर्ग के 'पूर्व की ओर देखो नीति' के लिए भारत से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक सड़क और रेल मार्ग बनाने (जो मणिपुर और म्यांमार से होकर गुजरेंगी) की अपनी योजना को लागू करने के लिए यह आवश्यक है।

मणिपुर के लोगों को सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी एकता और अपने साझा संघर्ष को मजबूत करना होगा, साथ ही, हम जो देश के बाकी हिस्सों में रहते हैं, उन्हें शासक वर्ग के झूठे प्रचार में नहीं आना चाहिए। हमें मणिपुरी लोगों और उनके अधिकारों के संघर्ष के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करना चाहिए। उनका संघर्ष यह सुनिश्चित करने के लिए कि संप्रभुता लोगों में हाथों में हो, राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन करने के हमारे साझा संघर्ष का एक हिस्सा है। हम लोगों को नीतियां और कानून बनाने और अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार होना चाहिए। हमें अर्थव्यवस्था को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से बदलकर नई दिशा में ले जाना होगा, न कि पूंजीवादी लालच को पूरा करने के लिए, जैसा कि आज हो रहा है।

संगीता, मुंबई

मज़दूर एकता लहर
हिंदोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 July, 2023, Date of publish - 1 July, 2023

To ....
....
....
....
....
....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

इस्राइल की सरकार द्वारा बस्तियों के तेज़ी से विस्तार की घोषणा

इस्राइली सरकार ने अपने क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक क्षेत्र में हजारों नए घरों वाली इस्राइली बस्तियों के निर्माण का तेज़ी से विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। 18 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मौजूदा प्रक्रियाओं को दरकिनार करने और इन बस्तियों के निर्माण में तेज़ी लाने के फ़ैसले की पुष्टि की। वेस्ट बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में 4,560 आवासीय घरों को बनाने की मंजूरी के लिए और योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, इस्राइल की सर्वोच्च योजना परिषद की जल्द ही बैठक होने वाली है।

इस्राइल ने 1967 के युद्ध में जिन फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा किया था – पूर्वी येरुशलम और वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और ग़ाज़ा पट्टी – उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्राइल को बार–बार वहां से हटने को कहा है।

इस्राइल के क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में सुनियोजित तरीक़े से यहूदियों की रिहायशी बस्तियों की स्थापना करना, यह इस्राइली राज्य द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ सबसे बड़े उकसावे वाले क़दमों में से एक है। यह सीधे तौर पर चौथे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, जिसके अनुसार, किसी क़ब्ज़ाकारी शक्ति को उसके द्वारा क़ब्ज़ा किए गए किसी भी क्षेत्र में अपनी आबादी को स्थानांतरित करने से रोका गया है। वर्तमान में इस्राइल के क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में अवैध तरीक़े से बसाई गई ऐसी लगभग 250 कॉलोनियां हैं, जिनमें 7.5 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं। इन्हें इस्राइली राज्य द्वारा सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस्राइली क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में इस्राइली बस्तियों के निर्माण और विस्तार की निगरानी इस्राइली सेना द्वारा की जाती है।

इस्राइल के क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में रहने वाले फिलिस्तीनियों को इस्राइली सुरक्षा बलों द्वारा चारों तरफ स्थापित की गई

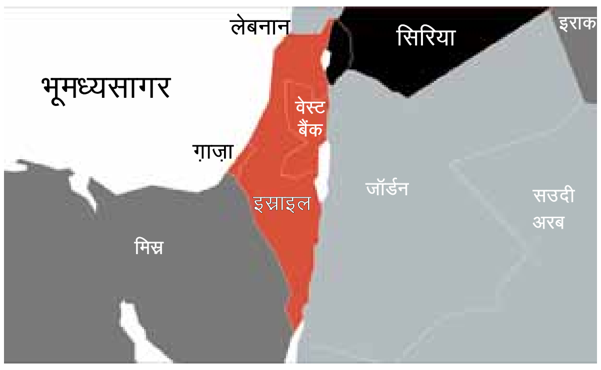

सैकड़ों चौकियों पर तलाशी के क्रूर और अपमानजनक तरीक़ों का हर रोज़ सामना करना पड़ता है। अपनी ज़मीन पर रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां अपना घर बनाने की अनुमति के लिए आवेदन करना पड़ता है। उन पर विध्वंस और बेदख़ली का ख़तरा लगातार बना रहता है। इस नई घोषणा से यह आशंका पैदा हो गई है कि जल्द ही पूरा वेस्ट बैंक क्षेत्र इस्राइल के नियंत्रण में आ जाएगा। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इस्राइल सरकार की योजना को "वेस्ट बैंक के क़ब्ज़े को पूरा करने के लिए तेज़ी से बढ़ाया जा रहा ख़तरनाक क़दम" बताया है।

नेतन्याहू की वर्तमान गठबंधन सरकार ने जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद से, मुख्य तौर पर उसके क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 7,000 नये आवासों को बनाने की मंजूरी दी है। इस्राइली सरकार ने एक क़ानून में संशोधन किया है ताकि पहले से क़ब्ज़ा की गयी चार बस्तियों, जिनमें बसाये गए लोगों को उन बस्तियों को खाली करना पड़ा था, उन चार बस्तियों में बसने वालों के वापस लौटने का रास्ता फिर से साफ़ किया जा सके।

इस्राइली राज्य ने दुनिया के मत की परवाह किए बिना, फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपने क़ब्ज़े और फिलिस्तीनी लोगों पर अपने हमलों को बड़ी हेकड़ी और बेशर्मी से जारी रखा है। वह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे अमरीकी साम्राज्यवाद का पूरा समर्थन प्राप्त है। अमरीकी साम्राज्यवाद इस्राइल को लगातार हथियारों से लैस करता रहता है। अमरीका संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्राइल की कार्रवाइयों का बचाव करने के लिए, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है।

अमरीका ने तेल समृद्ध पश्चिम एशियाई क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से, फिलिस्तीनी और अन्य अरब लोगों पर निशाना साधते हुए, इस्राइल को एक हथियार के रूप में बना रखा है। अमरीका नहीं चाहता कि इस्राइल, फिलिस्तीन और अन्य अरब देशों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहें। वह लगातार इस क्षेत्र में टकरावों और झगड़ों को बढ़ावा देता रहता है।

1948 में अपने निर्माण के बाद से ही, इस्राइली राज्य एक हमलावर और विस्तारवादी राज्य रहा है। नए इस्राइली राज्य ने अपने गठन के ठीक बाद, अपनी सेना को फिलिस्तीनी लोगों के क्षेत्रों पर हमला करने और उनकी भूमि पर क़ब्ज़ा करने के लिए भेजा था। बार–बार किये गये युद्धों के द्वारा, उसने फिलिस्तीनी लोगों की अधिक से अधिक भूमि पर क़ब्ज़ा कर लिया है। इस समय, 15 लाख से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब आदि देशों जैसे इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में फैले शरणार्थी शिविरों में अपना पूरा जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित इस्राइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता के ख़िलाफ़ किए गए अपराधों को न तो कभी भुलाया जा सकता है और न ही माफ़ किया जा सकता है। अपनी मातृभूमि पर अपने अधिकार की रक्षा के लिए, फिलिस्तीनी लोगों का इस्राइली हमले के ख़िलाफ़ संघर्ष पूरी तरह से जायज़ है। इसे दुनिया के सभी स्वतंत्रता–पसंद लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त है।

http://hindi.cgpi.org/23712

हिन्द–अमरीकी गठबंधन पर गोष्ठी

पृष्ठ 2 का शेष

बहाने देकर सरकारों का तख़्तापलट करना, आतंकवादी समूह तैयार करना, पैसा देना, हथियार देना, आदि, आदि। दुनिया में कहीं पर भी मज़दूरों और किसानों की क्रांति न हो – इस बात का ठेका अमरीका ने खुद लिया हुआ है। इसलिये अमरीका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता है। अलग–अलग बहानों से क्रांति को रोकने के लिये, कहीं पर भी जंग का मैदान बना देता है।

हमें, सभी मानवता पंसद, शांति पसंद, प्रगतिशील और इंसाफ पंसद लोगों का एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाकर अमरीकी साम्राज्यवाद को इस इलाके में घुसने से रोकना होगा।

प्रस्तुति का अंत इस नारे के साथ किया गया कि, "आओ हम सब मिलकर अमरीका–हिन्दोस्तान रणनैतिक गठबंधन को ठुकराएं!", "दक्षिणी एशिया में शांति बहाल करने के लिए, अमरीकी साम्राज्यवाद को भगाएं!" प्रस्तुति के बाद बाद चर्चा हुई।

कई वक्ताओं ने इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि साम्राज्यवादियों के क़दम को रोकने की ताक़त श्रमजीवी वर्ग में है। दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ी हिटलर की विशाल सेना को रूस के श्रमजीवी वर्ग ने बोल्शेविक पार्टी की अगुवाई में रोका था।

उन्होंने कहा कि अमरीकी साम्राज्यवाद का खूनी इतिहास काफी लंबा है। अमरीका ने आतंकवाद से लड़ने के बहाने "मुस्लिम समुदाय" के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जंग छेड़ रखा है। अमरीकी साम्राज्यवाद ने पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, इराक व अन्य देशों को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपति, अमरीकी साम्राज्यवाद की सहायता का इस्तेमाल करके दुनिया के कारखाने बतौर चीन की जगह लेना चाहता है।

वक्ताओं ने कहा कि हिन्दोस्तान–अमरीकी रणनैतिक गठबंधन से दक्षिण एशिया में कभी भी शांति नहीं होगी। यह गठबंधन दक्षिण एशिया के लोगों के ख़िलाफ़ है।

उन्होंने बताया कि देश का हुक्मरान वर्ग सरमायदार अपने साम्राज्यवादी मंसूबे को हासिल करने के लिये और दक्षिण एशिया में खुद की दादागिरी स्थापित करने के लिए देश के लोगों को साम्राज्यवादी जंग में झोंकना चाहते हैं। जबकि हमारे देश का संबंध नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान के साथ भ्रात्रिय और बराबरी के आधार पर होने चाहिएं।

वक्ताओं ने आगे कहा कि हमारे देश के श्रमजीवियों को उत्पादन के साधनों को अपने हाथों में लेकर, पूंजीवाद की जगह पर, हिन्दोस्तान में मज़दूरों–किसानों का राज स्थापित करके ही साम्राज्यवादी अमरीका को रोका जा सकता है।

सभा को संबोधित करने वालों में शामिल थे – हनुमान प्रसाद शर्मा, लोकपक्ष से के.के. सिंह, हरबंस सिंह पांधी, सुचरिता, प्रदीप चौहान, अधिवक्ता गौरव कुमार सिंह, अधिवक्ता नरेन्द्र पाठक, ईश्वर, शिवाजी, भरत सेठ, लोकेश। इसके अलावा, गोष्ठी में पाश, मनवीर और कृष्ण गुरुसरिया ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किए।

सभा का समापन करते हुए संचालक ने कहा कि हमारे देश में पूंजीपति वर्ग हुकूमत कर रहा है। मौजूदा सरकार पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा से, देश के पूंजीपति वर्ग का फ़ायदा है। इस यात्रा से हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग को कुछ नहीं मिलने वाला है। युद्ध के हथियारों पर खर्चा किया जाएगा। मज़दूरों और किसानों का जेबों को खाली किया जाएगा। इसके साथ ही इस इलाके की शांति को ख़तरे में डाला जाएगा।

संचालक ने कहा कि आज देश में मज़दूरों, किसानों, औरतों और नौजवानों के सामने समस्याओं का अंबार है। बेरोज़गारी बढ़ रही है। पूंजीपति वर्ग द्वारा मज़दूरों और किसानों के श्रम के फल को हड़प लिया जा रहा है। राज्य द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूख है, ग़रीबी है। समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य सेवा कल्पना की बात हो गयी है। देश के हुक्मरान वर्ग को देशवासियों की इन समस्याओं को हल करने में कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि है कि अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ मिलकर, वे इस इलाके में खुद की दादागिरी को स्थापित करने के मंसूबे को असली जामा पहनायें।

हम मज़दूर वर्ग के प्रतिनिधि हैं। हमें मज़दूर वर्ग का राज लाने की दिशा में किये जा रहे अपने काम को तेज़ करना होगा। अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ, हिन्दोस्तान के हुक्मरान वर्ग के साम्राज्यवादी मंसूबों का विरोध करना होगा, ताकि इस क्षेत्र को जंग के ख़तरे से बचाया जा सके।

http://hindi.cgpi.org/23720